क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक

क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्षः 1 अंकः 231, रविवार, 16 सितम्बर, 2018, पेजः 4, मुल्य 1 रु.

रजीस्ट्रड ऑफिसः- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

राष्ट्रभक्ति के प्रति बोहरा समाज की भूमिका अहम : मोदी

इंदौर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित सैफी मस्जिद का दौरा किया। बोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने मस्जिद के दरवाजे पर ही पीएम मोदी की अगवानी की और उन्हें मंच तक लेकर आए। पीएम मोदी को गले लगाकर सैयदना ने सैफी मस्जिद में उनका

इंदौर में बोहरा समुदाय की मस्जिद में पहुंचे पीएम, कहा-दिल और आत्मा को भी स्वच्छ रखना जरूरी

स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग दुनिया में हमारी वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत का जिक्रकरते हुए कहा कि हमें अपने दिल और आत्मा को भी स्वच्छ रखना है। दाऊदी बोहरा समुदाय की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को आपने अपने जीवन में उतारा है और सदियों से देश और दुनिया तक पैगाम पहुंचाया। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी।

उनकी यह सीख जितनी तब जरूरी थी, उतनी ही आज की दुनिया के लिए अहम है। पीएम मोदी ने कहा कि इन परंपराओं को मुखरता से प्रचारित करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि सैयदना साहब और बोहरा समाज का एक-एक जन इसमें जुटा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम की हमारे समाज और विरासत की यही शक्ति है कि हमें दुनिया के दूसरे देशों से अलग पहचान मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारी इस परंपरा से बोहरा समुदाय पूरी दुनिया को अवगत करा रहा है। मोदी बोले, मैं दुनिया में जहां भी जहां गया वहां शांति और विकास के लिए अपने समाज के योगदान की बातें जरूर करता हूं। शांति, सद्भाव, सत्याग्राह, राष्ट्रवाद और सौहार्द्र के प्रति बोहरा समुदाय की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण है।

सैफी विला में रुके थे महात्मा गांधी

पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की बोहरा समुदाय के सैयदना से मुलाकात हुई थी और इंदौर में सैफी विला में वह रुके थे। इस जगह को बाद में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। बोहरा समुदाय से मेरा पुराना नाता रहा है। आज भी मेरे दरवाजे आपके परिजनों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका और आपके पूरे परिवार का स्नेह मुझ पर बना रहेगा।

कुपोषण से जंग में बोहरा समुदाय ने दिया साथ

पीएम मोदी ने कहा कि आज से कुछ साल पहले मैंने एक कार्यक्रम में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए बोहरा समाज से सहयोग मांगा था। इसे भी बोहरा समाज और सैयदना साहब ने हाथों हाथ लिया। संयोग देखिए कि जब बोहरा समुदाय अशरा मुबारक के मौके पर जुटा है, तब पूरे देश में पोषण माह मनाया जा रहा है।

बोहरा समुदाय की कम्युनिटी किचन को सराहा

पीएम मोदी ने कहा कि कम्युनिटी किचन के माध्यम से बोहरा समाज यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि समाज का कोई व्यक्ति भूखा न सोए। आप लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कई अस्पताल चलाते हैं। आपके प्रयासों से अब तक 11,000 लोगों को अपना घर मिल चुका है। अब सरकार भी सबको घर देने की कोशिश में है। 2022 तक इस पर काम पूरा करने की योजना है। 1 करोड़ लोगों को अब तक हम घर की चाबी दे चुके हैं।

मुफद्दल सैफुद्दीन संग मंच तक आए पीएम मोदी

पीएम मोदी यहां शिया मुस्लिमों के दाऊदी बोहरा समुदाय के अशरा मुबारक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के साथ मस्जिद के द्वार से मंच तक आए। सैफी मस्जिद दाऊदी बोहरा समुदाय की मस्जिद है। बता दें नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए पीएम मोदी का यह दौरा और दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होना काफी अहम माना जा रहा है।

जासूसी मामले में नम्बी की गिरफ्तारी गैरजरूरी

- सुप्रीम कोर्ट का फैसला,कहा- 50 लाख मुआवजा दें
- दो वैज्ञानिकों पर गोपनीय दस्तावेज विदेश भेजने का आरोप था
- सीबीआई जांच में सामने आया था कि जासूसी हुई ही नहीं थी

नई दिल्ली (एजेंसी)। इसरो में 1994 में कथित जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वैज्ञानिक नम्बी नारायण को राहत दी। अदालत ने कहा कि नम्बी नारायण को गिरफ्तार किया जाना गैरजरूरी था, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने नम्बी नारायण को बरी कर दिया था। कांग्रेस ने इस मामले में

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण को निशाना बनाया था। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

नम्बी की गिरफ्तारी को सीबीआई ने गैरकानूनी करार दिया था : इस मामले में आरोप लगाए गए थे कि इसरो के दो वैज्ञानिकों समेत 6 लोगों ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के गोपनीय दस्तावेज विदेशों में भेजे थे। पहले पुलिस ने जांच की और फिर बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।

केवल मुआवजा काफी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि 76 वर्षीय नम्बी नारायण का मामला मानसिक प्रताड़ना से जुड़ा है। केरल सरकार 8 हफ्तों के भीतर उन्हें 50 लाख रुपए मुआवजा दे। अदालत ने कहा कि केवल मुआवजा दिया जाना ही पूर्ण न्याय नहीं है। बेंच ने इस मामले में केरल पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डीके जैन करेंगे।

माल्या मामला

एसबीआई की सफाई, हमारी तरफ से नहीं हुई ढील

नई दिल्ली (एजेंसी)। शराब कारोबारी विजय माल्या के हालिया बयानों पर हुए विवाद के बीच भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपनी सफाई पेश की है। एसबीआई द्वारा जारी बयान में कहा गया कि किंगफिशर से जुड़े लोन डिफॉल्ट केस से निपटने के लिए उनकी तरफ से कोई ढील नहीं हुई है। दरअसल, माल्या ने कुछ वक्त पहले एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लोन देने के मामले में बैंकों को भी दोषी बताया था। बैंक के बयान के आने से पहले यह बात भी सामने आई थी, कि एसबीआई ने फरवरी 2016 में बाकी सभी बैंकों (जिनसे माल्या ने कर्ज लिया हुआ है) को सलाह दी थी कि वह माल्या के देश छोड़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लें। लेकिन उस वक्त बैंकों ने एसबीआई की नहीं सुनी।

हॉवित्जर तोप 'के-9 वज्र-टी' ने 50 किमी दूर भेदा लक्ष्य

एडवांस्ड तोप का पोखरण फायरिंग रेंज में सेना ने फिर से किया परीक्षण

जयपुर (एजेंसी)। भारतीय सेना ने जोधपुर के पोखरण फायरिंग रेंज में गुरुवार शाम देश में निर्मित हॉवित्जर तोप के-9 वज्र-टी की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता का परीक्षण किया। पिछले परीक्षण के बाद इसमें 13 सुधार किए गए हैं। 40 से 50 किमी रेंज वाली इस तोप से छह गोले दागे गए। सभी गोलों ने अपने लक्ष्य पर अचूक प्रहार करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। सैन्य सूत्रों के अनुसार, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत वज्र को निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया है। सेना ने 155 एमएम की इस हॉवित्जर तोप के पिछले परीक्षण के दौरान कुछ सुधार करने को कहा था। सुधार के बाद एडवांस्ड तोप का पोखरण फायरिंग रेंज में सेना ने एक बार फिर से परीक्षण किया। यह तोप खास तौर से रेगिस्तान की परिस्थियों को ध्यान में रखकर विकसित की गई है। अगले कुछ दिनों में इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तोप को पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा।

देश में निर्मित हैं तोप के 50 प्रतिशत पुर्जे

लार्सन एंड टूब्रो ने दक्षिण कोरिया की कंपनी टेकविन के साथ मिलकर इस तोप का निर्माण किया

है। गुजरात के हजीरा में इसका कारखाना स्थापित किया गया है। तोप में 50 प्रतिशत सामग्री देश में ही निर्मित की गई है। सेना ने साढ़े चार हजार करोड़ में 100 तोपों का ऑर्डर दिया है।

कंपनी ने यह ऑर्डर वैश्विक स्तर पर जारी टेंडर में रूसी कंपनी को पछाड़ कर हासिल किया था। इन तोपों के मिलने के बाद सेना के पास हॉवित्जर तोप की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी।

'दहेज केस में पति की हो सकती है तुरंत गिरफ्तारी'

सेफगार्ड पर सुको का फैसला,कहा-पीड़ित की सुरक्षा के लिए यह जरूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दहेज उत्पीड़न के मामले में पति और उसके परिवार को मिला सेफगार्ड खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के अपने फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए पति की गिरफ्तारी का रास्ता भी साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि शिकायतों के निपटारे के लिए परिवार कल्याण कमिटी की जरूरत नहीं है। मामले में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत का विकल्प खुला है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक पुलिस सीआरपीसी की धारा 41 के तहत काम कर सकेगी, जिसमें पर्याप्त

आधार होने पर ही गिरफ्तारी का प्रावधान है। दहेज प्रताड़ना मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने पिछले साल दिए अपने फैसले में कहा था कि दहेज प्रताड़ना के केस में सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी लेकिन इस फैसले के बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा था कि दहेज प्रताड़ना मामले में दिए फैसले में जो सेफगार्ड दिया गया है उससे वह सहमत नहीं हैं। दो जजों की बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने दोबारा विचार करने का फैसला किया था और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

CJI की तीन जजों की बेंच में सुनवाई

13 अक्टूबर 2017 को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने कहा था कि इस मामले में दो जजों की बेंच ने 27 जुलाई को जो आदेश पारित कर तत्काल गिरफ्तारी पर रोक संबंधी गाइडलाइंस बनाई है उससे वह सहमत नहीं हैं। बेंच ने कहा था कि हम कानून नहीं बना सकते हैं बल्कि उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अदालत ने कहा था कि ऐसा लगता है कि 498ए के दायरे को हल्का करना महिला को इस कानून के तहत मिले अधिकार के खिलाफ जाता है। अदालत ने मामले में एडवोकेट वी. शेखर को कोर्ट सलाहकार बनाया था।

क्या था दो जजों की बेंच का फैसला

27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने कहा था कि आईपीसी की धारा-498 ए यानी दहेज प्रताड़ना मामले में गिरफ्तारी सीधे नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज प्रताड़ना मामले को देखने के लिए हर जिले में एक परिवार कल्याण समिति बनाई जाए और समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए उससे पहले नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना मामले में कानून के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की और लीगल सर्विस अथॉरिटी से कहा है कि वह प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण समिति का गठन करें। इसमें सिविल सोसायटी के लोग भी शामिल हों।

पहले के जजमेंट का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा था कि राजेश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस में गाइडलाइंस जारी किए थे और इसके तहत दहेज प्रताड़ना के केस में गिरफ्तारी से सेफगार्ड दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुको ने पहले अरनेश कुमार बनाम बिहार स्टेट के मामले में व्यवस्था दी थी कि बिना किसी ठोस कारण के गिरफ्तारी न हो यानी गिरफ्तारी के लिए सेफगार्ड दिए थे। लॉ कमिशन ने भी कहा था कि मामले को समझौतावादी बनाया जाए। निर्दोष लोगों के मानवाधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनचाही गिरफ्तारी और असंवेदनशील छानबीन के लिए सेफगार्ड की जरूरत बताई गई क्योंकि ये समस्याएं बदस्तूर जारी है।

दो जजों द्वारा दी गई गाइडलाइंस

- ऐसे मामले में न्याय प्रशासन को सिविल सोसायटी का सहयोग लेना चाहिए।
- देशभर के तमाम जिले में परिवार कल्याण समिति बनाई जाए और ये समिति जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाए।
- समिति में लीगल स्वयंसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर शख्स होंगे।
- जो भी केस पुलिस या मैजिस्ट्रेट के सामने आएगा, वह समिति को भेजा जाएगा।
- एक महीने में समिति अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट पर पुलिस व मैजिस्ट्रेट विचार के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी।
- जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी।
- अगर मामले में समझौता हुआ तो जिला जज द्वारा नियुक्त मैजिस्ट्रेट मामले का निपटारा कराएंगे और फिर मामले को हाई कोर्ट भेजा जाएगा ताकि समझौते के आधार पर केस बंद हो।

आर. के. पचौरी पर तय होंगे आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को टेरी के पूर्व प्रमुख आर के पचौरी के खिलाफ दायर मामले में छेड़छाड़ के आरोप तय करने का आदेश दिया है। पचौरी पर सहकर्मी द्वारा यह मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी। हालांकि, कोर्ट ने पचौरी को कुछ अन्य धाराओं से बरी कर दिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट चारू गुप्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354 ए (गलत तरीके से छूना और अश्लील टिप्पणी करने) और धारा 509 (अश्लील संकेत करने) के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। 2015 को पचौरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। फिर 21 मार्च को उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी। पीड़ित लड़की ने कोर्ट के ऑर्डर के बाद थोड़ी राहत मिलने की बात कही। उन्होंने कहा, यह आसान नहीं था। सच्चाई सामने लाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। बता दें कि 13 फरवरी 2015 में पचौरी की एक पूर्व साथी ने उनपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद फरवरी 2016 में एक अन्य महिला ने ऐसे ही आरोप लगाए। दूसरी महिला के मुताबिक, उनके साथ यह सब 10 साल पहले हुआ था। महिला ने TERI को उन्हें कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त करने की आलोचना भी की थी।

केस दर्ज होने के बाद पचौरी ने [illegible] के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, [illegible] की अंतरिम कमिटी द्वारा जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद वह इस संस्था में अपने पद पर बने रहे, जिसकी काफी आलोचना हुई थी।

भोपाल का बीयू बनाएगा 'आदर्श बहू', देगा सर्टिफिकेट

भोपाल (एजेंसी)। आपको एक संस्कारी बहू चाहिए, भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय आइए। जो विश्वविद्यालय यह निर्धारित नहीं कर पा रहा कि बीसीए स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा हिंदी में देंगे या अंग्रेजी में, उसने एक शॉर्ट टर्म कोर्स आदर्श बहुएं तैयार करने के लिए शुरू किया है। विश्वविद्यालय का मानना है कि यह कोर्स महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगला कदम है। आदर्श बहू तैयार करने का तीन महीने का यह कोर्स अगले अकादमिक सत्र से शुरू किया जाएगा। वाइस चांसलर प्रफेसर डीसी गुप्ता ने इस कोर्स का उद्देश्य बताते हुए कहा, इसका मकसद लड़कियों को जागरूक करना है जिससे वे नए माहौल में आसानी से ढल सकें। प्रफेसर गुप्ता ने कहा, एक विश्वविद्यालय के तौर पर हमारी समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमारा मकसद ऐसी दुल्हनें तैयार करना है जो परिवारों को जोड़कर रखें। यह सर्टिफिकेट कोर्स मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और महिला शिक्षा विभाग में पायलट प्रॉजेक्ट की तरह शुरू किया जाएगा। वह कहते हैं कि यह महिला सशक्तिकरण का एक हिस्सा है। कोर्स के पाठ्यक्रम के बारे में पूछने पर वीसी ने बताया, हम मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अन्य विषयों से जुड़े आवश्यक मुद्दों का समावेश कोर्स में करेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि कोर्स के बाद लड़की परिवार में होने वाले उतार-चढ़ाव को समझने के लिए तैयार रहे।

आज का विचार

30 लाख लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने

कभी-कभी कोई एक फैसला इतिहास बदल देता है। गुरुवार यानि 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हमेशा के लिए हटा दिया।

यानि अब बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने दो व्यस्कों के बीच बने समलैंगिंक यौन संबंध को एकमत से अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। संवैधानिक बेंच ने एकमत से ये फैसला सुनाया कि लैंगिक रुझान अपनी पसंद का मामला है। हर व्यक्ति को अपने शरीर पर पूरा अधिकार है। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दो व्यस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध को धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा- इन लोगों को इतने सालों तक समान अधिकार से वंचित रहना पड़ा, डर के साए में जीना पड़ा, इसके लिए इतिहास को इनसे माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा- समलैंगिकों को भी अपनी गरिमा के साथ जीने का पूरा अधिकार है, लोगों को अपना नजरिया बदलना होगा। समलैंगिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा- 158 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का कानून गरिमा के साथ जीने के अधिकार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद समलैंगिक समुदाय के लोग खुशी में झूम उठे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ लोग भले ही नाराजगी जता रहे हैं लेकिन इस एक फैसले से देश भर के समलैंगिकों को नई जिंदगी मिल गई है।

धारा 377 को पहली बार कोर्ट में 1994 में चुनौती दी गई थी। और आखिरकार 24 साल की लंबी लड़ाई के बाद समलैंगिकों को उनका हक मिल गया। अपनी मांगों को लेकर समलैंगिकों ने समय-समय पर देश भर में आंदोलन भी किया लेकिन उन्हें कभी किसी तरह का राजनीतिक समर्थन नहीं मिला। समलैंगिंकता को अपराध से बाहर रखने के लिए 2015 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर जरूर आए थे लेकिन तब बीजेपी सांसदों ने इसके विरोध में वोटिंग की थी। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में समलैंगिकों को अपनी आजादी से जिंदगी जीने का अधिकार हासिल है। कनाडा में 1969 में ही इसे कानूनी मान्यता मिल गई थी...वहां समलैंगिकों को आपस में शादी करने की भी अनुमति है। फ्रांस में 1791 से ही समलैंगिंकता को अपराध से बाहर रखा गया है, ब्रिटेन में 1967 में समलैंगिंको को उनका हक मिला तो अमेरिका में इसे 2003 में कानूनी मान्यता दी गई। रूस में 1993 से समलैंगिंको को साथ रहने का अधिकार है लेकिन वो शादी नहीं कर सकते। ब्राजील में 1830 से ही इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है.. वहां समलैंगिंको ककको आपस में शादी रचाने का भी अधिकार है।

भारतीय भाषाओं को दीजिए संरक्षण

ज्ञानेन्द्र रावत

हमारे देश में यह कहावत प्रचलित है कि यहां कोस-कोस पर पानी बदले और तीन कोस पर वाणी। कारण, भाषा के बदलाव की यह प्रकृति स्वाभाविक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह कहना था कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रख सकती है। इसी वजह से हिन्दी को उन्होंने राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि मुझे ऐसा लगता है कि यही एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्र की आत्मा को सहजता से व्यक्त कर सकती है। वह गुजराती थे और खुद गुजराती भाषी थे। अफ्रीका से भारत आने के बाद वह सबसे पहले बिहार में चंपारण गए। यहां उनको सबसे ज्यादा समस्या भाषा को लेकर हुई। उसके बाद तो उन्होंने अपने कुछ स्थानीय साथियों की मदद से हिन्दी सीखने की शुरुआत की।

देश के बंटवारे के बाद जब एक विदेशी संवाददाता ने उनसे दुनिया को संदेश देने का अनुरोध किया तो उनका यह स्पष्ट कहना था कि दुनिया को कह दो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। यह उनके हिन्दी प्रेम का परिचायक था। महात्मा गांधी ने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को हिन्दी से जोड़ने का गुरुतर और महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके चलते राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य राज्यों के दूसरे भाषा-भाषी शीर्ष नेताओं को भी अन्ततः हिन्दी को स्वीकारना ही पड़ा। इसे समय की विवशता या गांधीजी का व्यक्तित्व, कुछ भी कहें, उनको हिन्दी आखिरकार स्वीकारनी ही पड़ी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का कथन गौरतलब है कि उनका हिन्दी और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना गांधीजी की देन है। गांधीजी बोलने और लिखने में जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे, उसे वह हिन्दुस्तानी करार दिया करते थे। जबकि उस समय संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का बोलबाला था, बोलने-लिखने वाली भाषा सरल और सहज हिन्दी थी। उसे ही उन्होंने सम्पर्क भाषा के बतौर प्रयोग किया। विडम्बना है कि देश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान तो हासिल हुआ लेकिन हमने शिक्षा के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को अहमियत दी। इसका दुष्परिणाम असंतुलन, बिखराव, तनाव और बेगानेपन के रूप में हमारे सामने आया और इसे दूर करने के लिए आजादी के बाद इन 70 सालों में कोई सार्थक प्रयास हुए ही नहीं। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी की अनिवार्यता इसका जीता-जागता सबूत है।

सरकार इस बाबत दावे कुछ भी करे, असलियत यही है। इसके चलते ही हमारी देशज भाषाओं के पारंपरिक ज्ञान की अवहेलना हुई। मौलिक ज्ञान के सृजन में विफलता का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यह लगा कि हमारी मातृभाषाओं में देश के नौजवान को न तो रोजगार ही मिल पाना संभव है और न ही सम्मान हासिल हो सकता है। यही वह अहम कारण है कि आजादी के 70 साल बाद भी देश में अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है और आज अंग्रेजीदां लोगों को ही समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे देश में भाषा के नाम पर आंदोलन होते रहे हैं। भाषा के नाम पर राज्यों के गठन की मांग ही नहीं हुई, उनका गठन भी हुआ है।

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन के पीछे एक कारण राज्य में हिन्दी को लागू करने का प्रयास भी रहा। 1952 में श्रीमुलु ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर तमिलनाडु से अलग करने के लिए बड़ा आंदोलन चलाया, जिसकी अंततः परिणति अलग आंध्र के रूप में हुई। बॉम्बे प्रेसीडेंसी का बंटवारा भी गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर किया गया। आज स्थिति यह है कि देश में 1635 भाषाएं बोली जाती हैं। 234 मातृभाषाओं की पहचान सरकारी स्तर पर की गई है। 31 अन्य भाषाओं को विभिन्न सरकारों द्वारा मान्यता मिली है। करीब 100 भाषाएं देशभर में अलग-अलग जगहों पर एक लाख से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती हैं और 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। चिंता यही है कि देश में अगले पांच दशकों में कुल मिलाकर लगभग 400 भाषाओं पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। गौरतलब है कि आज 40 भाषाओं और बोलियों पर विलुप्ति के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यह खुलासा देश के जनगणना निदेशालय के अधिकारियों द्वारा किया गया है। साल 2002 में अंडेमान में 85 वर्षीय बोआ की मौत के बाद उनके द्वारा बोली जाने वाली अकाबो भाषा का अस्तित्व ही खत्म हो गया।

अब कहीं जाकर मैसूर स्थित केन्द्रीय भाषा संस्थान इन भाषाओं को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि हिन्दी को विस्तार दिलाने, उसकी जड़ें दक्षिण में जमाने, सरल भाषा में जन-जन तक पहुंचाने और भाषा के सेतु से उत्तर को दक्षिण से जोड़ने व हिन्दी पत्रकारिता में नए-नए शब्द गढ़ने में महात्मा गांधी के अलावा तमिलभाषी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मराठी भाषी गुणाकर मुले, तेलुगू भाषी बालशौरि रेड्डी और हिन्दी पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित बाबूराव विष्णु पराडकर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यदि हम अपनी मातृभाषाओं के महत्व, उनकी गरिमा को प्रतिष्ठित कर पाने में नाकाम रहे तो इनका नाम केवल इतिहास रह जायेगा।

कांग्रेस को तवज्जो ही नहीं दे रहीं सपा और बसपा, कैसे होगा महागठबंधन?

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भारत बंद पूरी तरफ से असफल रहा। कुछ एक जगह पर जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का प्रयास किया जरूर गया, लेकिन इमसें बंद समर्थकों को कोई सफलता नहीं मिली। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि तमाम व्यापारिक संगठनों ने एक दिन पूर्व ही बयान जारी करके कह दिया था कि उनका बंद से कोई लेना ?देना नहीं है। इसके अलावा बंद फ्लॉप होने के अन्य कारणों पर नजर डाली जाये तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का इस बंद से दूरी बनाए रखना भी था।

समाजवादी पार्टी ने भारत बंद के दिन अपने आप को प्रदर्शन तक सीमित रखा तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो भारत बंद के खिलाफ ही बयान देकर चौंका दिया। जिसकी उम्मीद कांग्रेस सहित किसी को नहीं थी। वैसे बंद को लेकर पूरे देश में भी कमोवेश यही स्थिति रही। बंद को सफल बनाने के लिये कई राज्यों में कांग्रेस सहित कुछ छोटे?छोटे दल आगजनी और तोड़फोड़ करते भी नजर आये, लेकिन ऐसे उत्पाती लोगों की संख्या कहीं भी 40?50 से अधिक नहीं नजर आई। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या भारत बंद गुजारे जमाने की बात होकर रह गई है या फिर जनता जानती समझती है कि कब ऐसे बंद उनके हितों के लिये और कब राजनैतिक स्वार्थवश बुलाए जाते हैं। भारत बंद का उत्तर प्रदेश में जो हश्र हुआ, वह सभी राजनीतिक दलों के लिए सबक है।

बंद नाकामयाब होने का यह मतलब नहीं है कि जनता के लिये पेट्रोल?डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह ऐसे गंभीर मसलों पर राजनीति भी नहीं पसंद करती है। आम आदमी जब ऐसे बंद के पीछे की असली मंशा समझने लगता है तो वह इसमें शामिल होना पसंद नहीं करता। राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिये देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, बीमार और बुजुर्ग लोगों के लिए समस्याएं खड़ी कराना, हिंसा, आगजनी, नागरिकों के साथ अभद्रता की घटनाओं के बीच राजनीतिक दलों को ऐसे किसी बंद या आंदोलन में नागरिकों की भागीदारी या समर्थन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अफसोसजनक है कि भारत बंद की वजह से बिहार में एक बीमार बच्ची की अस्पताल न पहुंच पाने के परिणामस्वरूप मौत हो जाती है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी या उनके प्रवक्ता खेद में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, जबकि भारत बंद के आयोजकों को पीड़ित परिवार से न सिर्फ मांफी मांगनी चाहिए बल्कि उनकी मदद भी करनी चाहिए। कांग्रेस और उसके बंद समर्थक सहयोगी दलों को स्पष्ट करना चाहिए था कि क्या पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि का विरोध बंद के अलावा किसी अन्य लोकतांत्रिक ढंग से नहीं किया जा सकता था। आज कांग्रेस पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ने पर इनको जीएसटी के दायरे में लाने की मांग मोदी सरकार से कर रही है, लेकिन जब वह सत्ता में थी तो वह भी पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने को सहमत नहीं थी। इसके अलावा कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना होगा कि उसने भारत बंद के लिये 10 सितंबर का ही दिन क्यों चुना जिस दिन नेशनल हेराल्ड केस में अदालत में सुनवाई होनी थी। कहीं इसके पीछे की मंशा यह तो नहीं थी कि भारत बंद के शोर में अदालत की कार्रवाई अखबारों की सुर्खियां न बटोर पाये। अगर ऐसा था तो कांग्रेस इसमें काफी सफल रही।

कांग्रेस को इस बात पर भी जवाब देना चाहिए कि जब उसके अध्यक्ष राहुल गांधी बार?बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार से जनता ऊब चुकी है तो जनता उनमें (राहुल गांधी) विश्वास क्यों नहीं दिखा रही है। बहरहाल, उत्तर प्रदेश में भारत बंद विफल रहने का सबक कांग्रेस के अलावा उन सभी दलों के लिए है जो समय-समय पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे हथकंडों का सहारा लेते हैं। लोकतंत्र में कोई भी आंदोलन जन?समर्थन के बिना सफल नहीं हो सकता। यदि आम आदमी आंदोलन के साथ नहीं तो ऐसे आंदोलन का क्या मतलब ? राजनीतिक दलों को चाहिए कि भविष्य में कोई भी आंदोलन करने से पहले यह विचार जरूर करें कि उनकी रणनीति जनता को पसंद आएगी या नहीं।

यहां समाजवादी पार्टी और बसपा की भी चर्चा जरूरी है, जिनके सहारे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बंद सफल होने की उम्मीद लगाये बैठी थी। पहले बाद समाजवादी पार्टी की कि जाये तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का शायद आंदोलनों में विश्वास ही नहीं है। वह आंदोलन के नाम पर लकीर पीटते ही दिखाई देते हैं।

इस बात को उनके चाचा और समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के अध्यक्ष शिवपाल यादव द्वारा गत दिनों दिये गये एक बयान से भी समझा जा सकता है, जब शिवपाल ने एक सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में भतीजे अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा, %जब हाईस्कूल में था, तब से नेताजी के साथ काम करने लगा था। चुनाव में 90-90 किलोमीटर साइकिल चलाकर नेताजी का प्रचार करता था। आज लोग एक घंटा साइकिल चला देते हैं तो बताते हैं कि बड़ा काम कर दिया। शिवपाल यहीं नहीं रूके और बोले, महाभारत धर्म युद्ध था। कंस ने धर्म का पालन नहीं किया। बहन, बहनोई और पिता को कैद में डाल दिया। आज भी बहुत से कंस पैदा हो जाते हैं। एक कंस आज भी है।

उनके अंदाजे बयां से यह समझना मुश्किल नहीं था कि उनका निशाना कहां था। खैर, बसपा सुप्रीम मायावती ने भारत बंद के दूसरे दिन यानी 11 सितंबर को जो बयान दिया। उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में नयी गर्मी पैदा करके लोगों को यह सोचने को भी मजबूर कर दिया कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अलग?थलग पड़ रही है। महागठंबधन की बात अभी बेमानी है। मायावती का कहना था कि पेट्रोल?डीजल की आसमान छूती कीमतों के लिए कांग्रेस और भाजपा की सरकारें बराबर की कसूरवार हैं, दोनों की नीतियां एक जैसी हैं। कांग्रेस की संप्रग सरकार ने जून 2010 में पेट्रोल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया था। मोदी सरकार ने सत्ता हासिल करने के कुछ माह बाद ही 18 अक्टूबर, 2014 को डीजल को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया। इन गरीब व किसान विरोधी फैसलों को बड़े आर्थिक सुधार के रूप में दुनिया के सामने पेश किया गया, जिसका नतीजा सब के सामने है। बसपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ना केवल कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों को लागू करती रही, वरन इनसे आगे बढ़ नोटबंदी और जीएसटी को अपरिपक्व ढंग से देश पर थोपा दिया।

इसी कारण सवा करोड़ देशवासियों का जीवन नारकीय होता जा रहा है। मायावती ने चेताया कि जिस तरह से जनता ने वर्ष 2014 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था उसी तरह भाजपा को भी 2019 में सजा देगी। उधर, नोटबंदी तथा जीएसटी और मोदी?योगी सरकार पर बसपा अध्यक्ष मायावती की टिप्पणी पर भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि नोटबंदी लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने इसका विरोध करने की सजा बसपा को 19 सीट पर समेट कर दी थी। वहीं, कांग्रेस के साथ मिलकर कुशासन और भ्रष्टाचार का भागीदारी करने की सजा बसपा को 2014 में शून्य पर पहुंचने के जरिये मिली थी। डॉ. पांडेय ने कहा कि किसानों के लेकर बहन जी के बहाये जा रहे घड़ियाली आंसू की हकीकत जनता को पता है।

भट्टा पारसौल में निर्दोष किसानों पर उन्होंने ही अपने शासन में गोलियां चलवाई थीं। लब्बोलुआब यह है कि बीजेपी विरोधी दलों के बीच अभी भी एकजुटता का अभाव नजर आ रहा है। इसके पीछे के कारण छिपे हुए भी नहीं हैं, जबकि सपा के बागी नेता शिवपाल यादव ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चे का गठन करके बीजेपी विरोधियों की गोलबंदी में एक नया एंगल जोड़ दिया है। इससे समाजवादी पार्टी प्रभावित होने से बच नहीं पायेगी। इस बात का अहसास मायावती को भी है। इसी के बल पर वह सपा से चुनावी गठबंधन होने की दशा में अपने हिसाब से सीटों के लिये मोलभाव कर सकती हैं। कांग्रेस से बसपा की दूरी बनाकर चलना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। वह सीटों में ज्यादा बंदरबांट नहीं चाहती है।

चीन में दमन से अमन की रणनीति

देवाशीष चौधरी

1990 के दशक में हिंसा की छिटपुट घटनाएं जरूर हुई थीं, मगर झिंजियांग 2008 तक अमूमन शांत ही था। उसी वर्ष तिब्बत अशांत हुआ और ल्हासा में दंगे भड़के। 2013 और 2015 के बीच हिंसक घटनाओं में फिर से तेजी आई। मार्च 2016 में झिंजियांग के तत्कालीन पार्टी सचिव झांग चुंशियन ने दावा किया कि झिंजियांग में 'हिंसक आतंकवाद' में तेजी से कमी आई है और सरकार ने सुरक्षात्मक उपाय मजबूत किए हैं। मगर झांग की वहां से अचानक विदाई हो गई, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि केंद्रीय नेतृत्व झिंजियांग पर आखिर कैसा शासन करना चाहता है और सख्त नीतियां अपनाकर सरकार क्या हासिल करना चाहती है?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 17 जनवरी, 2017 को दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उस वक्त के अंतरराष्ट्रीय हालात की व्याख्या चार्ल्स डिकेंस की प्रसिद्ध पंक्ति 'यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था' के जरिए की थी। यह पंक्ति किसी खास दौर के विरोधाभासों का बयान करने के लिए उपयुक्त है। विडंबना है कि ह्यूमन राइट वाच की ताजा रिपोर्ट आने के बाद चीनी प्रांत झिंजियांग के बारे में भी यही कहा जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि झिंजियांग में चेन क्वांगुओ के पार्टी सचिव बनने के बाद से उइगर समुदाय इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जबकि दूसरी तरफ, सुरक्षा के तमाम बड़े ताम-झाम और अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली संकेत देते हैं कि 'ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट' जैसी उइगर-ताकतें चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी हैं।

ऐसे में झिंजियांग की सच्चाई को परखना जरूरी हो गया है। 5 जुलाई, 2009 के उरुमकी दंगों से पहले तक झिंजियांग में अलगाववादी हिंसा का कोई बड़ा निशान नहीं था। 1990 के दशक में हिंसा की छिटपुट घटनाएं जरूर हुई थीं, मगर झिंजियांग 2008 तक अमूमन शांत ही था। उसी वर्ष तिब्बत अशांत हुआ और ल्हासा में दंगे भड़के। 2013 और 2015 के बीच हिंसक घटनाओं में फिर से तेजी आई। मार्च 2016 में झिंजियांग के तत्कालीन पार्टी सचिव झांग चुंशियन ने दावा किया कि झिंजियांग में 'हिंसक आतंकवाद' में तेजी से कमी आई है और सरकार ने सुरक्षात्मक उपाय मजबूत किए हैं। मगर झांग की वहां से अचानक विदाई हो गई, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि केंद्रीय नेतृत्व झिंजियांग पर आखिर कैसा शासन करना चाहता है और सख्त नीतियां अपनाकर सरकार क्या हासिल करना चाहती है? 2011 के शुरुआती महीनों में हुई कथित 'जैस्मीन क्रांति' के बाद झिंजियांग के सामाजिक प्रबंधन के लिए ऐसे कई संगठन बनाए गए, जिनका मकसद संदिग्ध तत्वों, धर्मगुरुओं, अपराधियों, अलगाववादियों और आतंकियों पर नजर रखना था। झिंजियांग और चीन के दूसरे हिस्सों में 2013-14 के दौरान हुई सिलसिलेवार हिंसक घटनाओं के बाद झिंजियांग

सरकार ने इस क्षेत्र में सुरक्षात्मक हालात सुधारने के लिए कई कदम उठाए। केंद्रीय नेतृत्व ने उइगर अलगाववादियों के खिलाफ 'जंग' की घोषणा की और शी जिनपिंग ने इन्हें पकड़ने के लिए 'तांबे और स्टील की दीवार बनाने' और 'जमीन से आसमान तक नेट' लगाने के आदेश दिए।

इस बीच, चेन क्वांगुओ 'जातीय नीति के नए प्रवर्तक' के रूप में चर्चित हो चुके थे। वह तिब्बतियों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) का नियंत्रण मजबूत बनाने के नए तरीके ईजाद कर चुके थे। तिब्बत में उनकी सफलता ही वजह थी कि उइगर अलगाववादियों का वास्तविक और काल्पनिक खतरा खत्म करने की जिम्मदारी उन्हें दी गई। इसके बाद, केंद्रीय और क्षेत्रीय हुकूमतों ने कई ऐसे कानून बनाए, जिनके तहत उइगर की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां अपराध के दायरे में आ गईं। इनमें चीन का आतंकवाद निरोधी कानून (दिसंबर, 2015), झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र (एक्सयूएआर) का आतंकवाद निरोधी कानून (अगस्त, 2016) और एक्सयूएआर रेगुलेशन ऑन डी-रेडिकलाइजेशन (मार्च, 2017) उल्लेखनीय हैं। ये कानून स्थानीय प्रशासन को निगरानी और सेंसरशिप का असीमित अधिकार देते हैं। इन कानूनों के तहत उइगर विचारों और उनके कार्यक्रमों पर नजर तो रखी ही जाने लगी, नकाब व बुरका पहनने, दाढ़ी बढ़ाने, बच्चों के धर्म से जुड़े नाम रखने आदि को आपराधिक व्यवहार बताकर उन पर पुलिसिंग शुरू हो गई। चेन ने झिंजियांग में 'कनवीनियंस पुलिस स्टेशन' की स्थापना की, ताकि सरकार अधिक से अधिक निगरानी और स्थानीय समुदायों पर नियंत्रण रख सके। इस स्टेशन के पास दंगा रोकने के अत्याधुनिक उपकरण भी हैं और आवाज व चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर जैसी अत्याधुनिक निगरानी व्यवस्था भी।

चेन प्रशासन ने 'डबल लिंक्ड हाउसहोल्ड' सिस्टम की भी शुरुआत की, जो एक-दूसरे के घर में ताक-झांक की अनुमति देता है। स्थानीय आंदोलनों को दबाने के लिए झिंजियांग अधिकारियों ने बड़ी संख्या में उइगरों के पासपोर्ट जब्त किए और विदेशों में पढ़ रहे ज्यादातर उइगर नौजवानों को वापस मुल्क लौटने का फरमान सुनाया। कहा जाता है कि इनमें से अनेक छात्रों को वापस लौटने के बाद हिरासत में लिया गया और फिर उनका पता नहीं चला। झिंजियांग में उइगरों के संदिग्ध व्यवहारों पर नजर रखने वाला साइबर निगरानी तंत्र भी है। यह उइगरों द्वारा किए जाने वाले तमाम इंटरनेट कम्युनिकेशन इकट्ठे करता है। पर्सनल कम्युनिकेशन की निगरानी, स्मार्टफोन पर नजर, निजी गाड़ियों पर जीपीएस व रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी टैग की अनिवार्यता भी आम कर दी गई है।

पिछले साल से तो झिंजियांग पुलिस लोगों के डीएनए जमा करने की योजना पर भी खासी सक्रिय है। यहां 2017 की शुरुआत में 'काउंटर-टेररिज्म ट्रेनिंग स्कूल' और 'एजुकेशन ऐंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर' की स्थापना की गई, जहां हर उम्र के हजारों उइगर और अन्य मुस्लिम समुदायों को दोबारा पढ़ाई के लिए भेजा गया। जिस ह्यूमन राइट वाच रिपोर्ट की आज चर्चा हो रही है, वह 58 लोगों के इंटरव्यू पर आधारित है। इनमें से पांच ऐसे हैं, जो इन शिक्षा शिविरों में कैद थे, जबकि 38 उन लोगों के परिजन हैं, जो अब भी इन शिविरों में बंद है। जातीय खांचे से देखें, तो इंटरव्यू देने वाले 32 कजाक थे, 23 उइगर, एक हुई और एक-एक उज्बेक व किर्गीज। वाच की रिपोर्ट यह भी बताती है कि नया दमनकारी शासन अब अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सामाजिक जीवन पर बंदिशें लगा रहा है। केंद्रीय शासन के शुरुआती दौर के बाद, प्रशासन का उद्देश्य विभिन्न मुस्लिम समुदायों के बीच खाई बनाना था। और चूंकि 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में झिंजियांग में अलगाववादी हिंसा शुरू हो चुकी थी, इसीलिए सरकार ने बड़ी आसानी से उइगरों को 'परेशानी पैदा करने वाले लोग' साबित कर दिया। बावजूद इसके अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि 'धार्मिक चरमपंथी व हिंसक अतिवादी मानसिकता और वैचारिक बीमारी को दुरुस्त करने की' चेन की रणनीति सही है, क्योंकि दमन की यह रणनीति ही झिंजियांग के विभिन्न मुस्लिम गुटों को एकजुट कर सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मैं सौ जन्म में छुटकी जैसी पटाखा नहीं बन सकती

आमिर खान की 'दंगल' में कमाल दिखा चुकीं सान्या मल्होत्रा खुद को लकी मानती हैं कि करियर की शुरुआत में ही उन्हें आमिर और विशाल जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला है। वह कहती हैं, 'मैं तो खुद को खुशनसीब मानती हूं कि 'दंगल' करने के बाद करियर के इतने कम समय में ही मैं दो और फिल्में कर रही हूं। इस पर सोने पर सुहागा यह हुआ कि मुझे विशाल भारद्वाज सर के साथ काम करने का मौका मिला।

विशाल हमेशा से मेरे पसंदीदा डायरेक्टर रहे हैं। मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहती थी। उनकी फिल्में और गानों ने हमेशा से मुझे प्रेरित किया है। उनके साथ काम करना मेरे लिए सपने जैसा है, जिसपर आज भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे आज भी याद है, 'हैदर' देखने के बाद मैं थिअटर में 15 मिनट सुन्न होकर बैठी रही और सोचती रही कि कब मैं इनके साथ काम कर पाऊंगी।

दिल्ली से ऐक्टिंग का सपना लेकर आना और करियर की शुरुआत में ही दो बड़े बैनर मिल जाना। कितना खुशनसीब मानती हैं खुद को?

मैं खुद को भगवान का बच्चा मानती हूं। मैं जिंदगीभर उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। उन्होंने मुझे वह दिया जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। मुझे यह जिंदगी जीने में बड़ा मजा आ रहा है। सुबह जब भी उठती हूं तो सोचती कि मैं कितनी खुशनसीब हूं। ऐसा मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है। बहुत से लोग मुंबई आते हैं लेकिन उन्हें ऐसा मौका मिल नहीं पाता है। रही बात आगे जाने की तो मैं नहीं जानती कि कब तक करूंगी। मैं जब तक यहां हूं बस अच्छा काम करना चाहती हूं। मुझे कुछ बन जाने की कोई जल्दी नहीं है। बहुत फेमस होने का सपना मैं नहीं देखती। मैं कैमरे के सामने ज्यादा सुकून महसूस करती हूं।

फिल्म से कैसे जुड़ना हुआ?

मैं 'बधाई हो' की शूटिंग कर रही थी। इसी बीच मैनेजर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि विशाल सर दिल्ली में हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं सेट पर थी और वह सेट पर आए। मेरी उनसे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान मैंने सेंस कर लिया कि वह मुझसे ज्यादा इंप्रेस नहीं हैं। उन्होंने जरूर सोचा होगा कि मैं तो बड़ी शांत सी हूं, उनकी फिल्म की छुटकी के किरदार के लिए शायद फिट नहीं बैठ पाऊंगी। मुझे 3 सीन दिए गए थे और ऑफ डे पर मुझे ऑडिशन देने को कहा गया। मेरे जन्मदिन के दिन मुझे ऑफ मिला था। मुझे याद है उस दिन शाम को विशाल सर का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको डायलॉग बोलने में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपके साथ रिहर्सल कर लेता हूं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने विशाल जी के साथ फिल्म की रिहर्सल की। अगले दिन मैंने ऑडिशन दिया और उन्हें पसंद आया। सच कहूं, मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं था कि मैं इस फिल्म में काम करूंगी। लेकिन एक तसल्ली तो जरूर थी कि चलो विशाल सर मुझे जान गए हैं तो कभी न कभी किसी न किसी फिल्म में मौका तो जरूर दे देंगे।

'दंगल' में भी आप लड़ाई करती थीं और यहां भी बहन से लड़ती रहती हैं?

'दंगल' और 'पटाखा' की लड़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। कहानी में दो बहनों का कॉन्सेप्ट जरूर एक सा है लेकिन बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क है। बबीता गीता से कभी ऐसी बात नहीं करेगी जिस तरह छुटकी अपनी बहन से बात करती है। 'दंगल' में हमारे लिए सबसे जरूरी यह था कि हम एक प्रफेशनल रेसलर दिखें। वहीं इस फिल्म के साथ समस्या है कि मुझे वैसी लड़की का किरदार निभाना था जो कभी मैं सौ जन्म में नहीं बन सकती। मैं बहुत ही शांत और कम बोलने वाली लड़की हूं जो छुटकी से काफी अलग है। अपने कम्फर्ट जोन से निकलकर इस तरह का किरदार निभा पाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए मैंने बहुत वर्कशॉप किए जो मेरे लिए काफी मददगार साबित हुए। मैं हमेशा से इस तरह का किरदार करना चाहती थी जिसमें मैं चिल्ला सकूं।

ट्रेलर में आप राधिका से मारपीट करती नजर आ रही हैं। ऑफ स्क्रीन आप दोनों की ट्यूनिंग कैसी थी?

मैंने यही सोचा था कि जबतक शूटिंग होगी हम तब तक साथ होंगे। एक बेहद ही प्रफेशनल को-स्टार की तरह काम करेंगे। जब वर्कशॉप शुरू हुई तो राधिका और मैं एक दूसरे को काफी हेल्प किया करते थे। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। यह बॉन्डिंग सीन के शूटिंग में दिखती थी। शूटिंग के वक्त हम ऐक्टिंग नहीं कर रहे होते थे बल्कि हम बातचीत कर रहे होते थे। जो स्क्रीन पर काफी नेचुरल लगता था। राधिका बेहद ही पॉजिटिव इंसान हैं। हर कोई ऐसी दोस्त चाहेगा और मैं खुशनसीब हूं कि मुझे राधिका जैसी को-ऐक्टर के रूप में एक अच्छी दोस्त मिली है।

आमिर के साथ अब कैसी बॉन्डिंग है। बातचीत होती है आपकी?

मैंने अपने करियर की शुरुआत आमिर सर, नितेश सर और किरण मैम के साथ की थी। इन सबसे मेरा बेहद ही इमोशनल कनेक्शन है। मुंबई में अगर मेरी कोई फैमिली है तो यही है। आमिर सर बहुत बिजी होते हैं, तो उन्हें बात-बात पर डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। हमारा एक वॉट्सऐप ग्रुप है, जहां हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। मैं अपने प्रॉजेक्ट्स और उसकी इंफॉर्मेशन उनसे शेयर करती हूं। हाल ही में मैंने एक घर और कार खरीदी है। मैंने यह खुशी उनसे शेयर की। वे सभी मेरे लिए खुश हैं।

ऋतिक के साथ बेस्ट परफार्मेंस देना चाहते हैं टाइगर

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्राफ माचो मैन ऋतिक रौशन के साथ अपना बेस्ट परफार्मेंस देना चाहते हैं। बॉलीवुड निर्देशक सिद्धार्थ आनंद एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें ऋतिक, टाइगर श्राफ और वाणी कपूर की अहम भूमिका है। टाइगर ने कहा है कि वह फिल्म में ऋतिक के साथ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। टाइगर ने कहा, मैं बेहतरीन होना चाहता हूं, क्योंकि वह हमेशा बेहतर करते हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वह सहज भी होंगे। बता दें चर्चा थी कि फिल्म में दोनों डांस करते दिखेंगे, लेकिन टाइगर का कहना है कि इस बारे में कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा, हमने अभी कोई गीत तैयार नहीं किया है, लेकिन फिल्म में दिलचस्प सिचुएशन है, जहां दोनों डांस फ्लोर पर साथ आते हैं।

संजू को लेकर राजकुमार हिरानी ने किया ये बड़ा खुलासा

फिल्मकार राजकुमार हिरानी ने खुलासा किया है कि अभिनेता संजय दत्त पर आधारित फिल्म 'संजू' में अतिरिक्त हिस्सा जोड़ा गया ताकि लोगों में उनके प्रति फैली 'नफरत' की भावना को सहानुभूति में बदला जा सके। हिरानी ने बताया कि शुरूआती संपादित फिल्म में अभिनेता की कहानी को जस का तस दिखाया गया था और उसे लोगों ने पसंद नहीं किया था। उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान उन्हें लगा 'मैं क्या कर रहा हूं। मैं गलत दिशा में जा रहा हूं।' वास्तव में जब पहला संपादन तैयार हुआ और हमने लोगों के लिए उसकी स्क्रीनिंग रखी तो उन्होंने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते और वे इसे नहीं देखना चाहते। निर्देशक ने यह भी बताया कि वह चाहते थे कि सच्ची कहानी दिखायी जाए क्योंकि वह उसके (संजय) प्रति किसी तरह की सहानुभूति नहीं पैदा करना चाहते थे। उन्होंने आरंभ में उसे वैसा ही दिखाया जैसा वह है। लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि वह हमारा नायक है और हमें उसके लिए कुछ सहानुभूति रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपने मुख्य चरित्र के लिए सहानुभूति बनाने को फिल्म में कुछ हिस्से जोड़े गए जो पहले इसमें नहीं थे। उन्होंने बताया कि अदालत का फैसला आने के बाद खुद की जान लेने की कोशिश करने वाला हिस्सा फिल्म में नहीं था जिसे बाद में फिल्माया गया। यह मूल पटकथा में नहीं था। उनका सोचना है कि इससे कुछ सहानुभूति मिलेगी। उन्होंने कहा कि हर फिल्म एक यात्रा होती है। कुछ चीजों पर काम किया जाता है और कुछ पर नहीं। उन्हें अभी भी इस फिल्म में कमियां दिखाई देती हैं लेकिन आप अपना बेहतर देने की कोशिश करते हैं।

महिलाओं को अपनी खूबसूरती पर गर्व होना चाहिए

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर हाल ही में एक ब्यूटी प्रोडक्ट के लॉन्च में पहुंची। यहां उन्होंने महिलाओं के लिए बात की। उन्होंने कहा, जब बात खूबसूरती की आती है तो हर महिला का अलग सफर होता है और उन्हें इस पर गर्व होना चाहिए। उन्हें किसी को फॉलो करने की जरुरत नहीं है क्योंकि दो चीजें कभी एक जैसी नहीं हो सकती और इसी तरह इसे लेकर ग्लानि नहीं होनी चाहिए। यह इंसान का स्वभाव है कि आप कैसे दिखते हैं उस पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। यह आत्म अभिव्यक्ति का तरीका है। मेरी इसमें काफी रूचि है। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने अपनी मां को शूट और कार्यक्रमों के लिए तैयार होते देखा। जीवंत यादों में से एक यह है कि वह बहुत अच्छी तरह मेकअप करती थीं। बता दें कि जाह्नवी सादा रहना पसंद करती है और अक्सर अच्छी त्वचा के लिए घरेलू नुस्खे अपनाती हैं। जाह्नवी अब करण जौहर की फिल्म 'तख्त' में दिखाई देंगी, जिसमें उनके साथ करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, विक्की कौशल और भूमि पेडनेकर हैं।

...तो क्या सच में श्रद्धा कपूर के पास प्यार के लिए नही है वक्त?

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का कहना है कि अभी उनके पास प्यार करने के लिये वक्त नहीं है। श्रद्धा की फिल्म 'स्त्री' हाल ही में प्रदर्शित हुई है जो हिट साबित हुई है। श्रद्धा इन दिनों 'बत्ती गुल मीटर चालू' में काम कर रही हैं। उनका कहना है कि बैक टू बैक प्रॉजेक्ट के कारण उनके पास प्यार ढूंढने या इस टॉपिक पर ध्यान देने के लिए भी समय नहीं है। श्रद्धा ने कहा कि वह यदि रिलेशनशिप में जाती हैं तो उसे पूरा समय और ध्यान देना चाहेंगी, जो फिलहाल उनके लिए संभव नहीं है। बिजी होने के बाद भी श्रद्धा खुद के लिए थोड़ा समय निकालना नहीं भूलतीं। इन दिनों वह बैडमिंटन सीख रही हैं। श्रद्धा यह गेम सायना नेहवाल की बायॉपिक के लिए सीख रही हैं, जिसमें वह लीड किरदार निभाती नजर आएंगी। प्रैक्टिस के लिए श्रद्धा रोज सुबह छह बजे उठ जाती हैं। श्रद्धा फ्री टाइम मिलने पर गाने भी लिखती हैं। साथ ही उनके लिए म्यूजिक भी कंपोज करती हैं। श्रद्धा ने कहा कि फिल्म प्रॉजेक्ट से ब्रेक मिलने पर वह अपने गोवा के हॉलिडे होम में समय बिताना चाहेंगी। इस घर को श्रद्धा ने हाल ही में खरीदा है।

दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रही है करीना, लेकिन...

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर हाल ही में अमृता अरोड़ा के साथ कोमल नहाटा के शो में पहुंची। यहां उन्होंने काफी बातें की। शो में करीना से उनके दूसरे बच्चे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि- 'मैं और सैफ दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे है लेकिन 2 साल बाद'। तभी अमृता ने तुरंत कहा- मैंने करीना को कह दिया है जब वो दोबारा से प्रेग्नेंट होने का फैसला करेंगी तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं ये देश छोड़कर चली जाऊंगी। इन दिनों करीना का बेटा तैमूर सबकी आंखों का तारा बना हुआ है। करीना से ज्यादा अक्सर तैमूर सुर्खियां बटोरता है। तैमूर की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। काम की बात करे तो करीना हाल ही में फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' में नजर आई थी। वहीं करीना जल्द ही फिल्म 'तख्त' और अक्षय कुमार के साथ 'गुडन्यूज' में नजर आएंगी।

धारा 377 पर बेस्ड फिल्म करना चाहते हैं आयुष्मान

अभिनेता आयुष्मान खुराना पिछले एक हफ्ते से खूब खबरों हैं। वजह है रिलीज के लिए तैयार उनकी दो फिल्में 'बधाई हो' और 'अंधाधुन', दोनों ही फिल्मों का जॉनर एकदम अलग है। विचित्र तरह के विषयों की फिल्मों में काम करने के लिए मशहूर आयुष्मान इन दिनों 'बधाई हो' के ट्रेलर पर जमकर मिल रही वाहवाही का जश्न मना रहे हैं। अपनी फिल्म के बारे में बातचीत के दौरान आयुष्मान ने कहा कि वह आगे भी ऐसी ही अलग तरह की कहानियों पर काम करते रहेंगे। आयुष्मान ने सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में धारा 377 पर दिए गए पॉजिटिव और एतिहासिक फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि अगर कभी ख्रक्षद्दड्ड और धारा 377 के विषय पर कोई अच्छी कहानी मिलेगी तो उस विषय पर भी काम करना चाहेंगे। आयुष्मान आगे कहते हैं, 'मुझे लगता है धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सचमुच ऐतिहासिक फैसला है। यह फैसला बहुत पहले ही हो जाना था। यह फैसला यह दिखाता है कि हम प्रोग्रेसिव भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इस फैसले के बाद भारतीय न्याय प्रणाली पर हमारा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है। अभी भी कुछ छोटी-छोटी लड़ाइयां बाकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो पॉजिटिव फैसला सुनाया है, लेकिन सामाजिक रूप में इसे लोग अच्छी तरह समझ लें और अपना लें तब असली जीत होगी। हमें लोगों को इस विषय पर शिक्षा देनी होगी। अगर इस विषय पर कोई फिल्म बनेगी तो बिल्कुल करना चाहूंगा, क्यों नहीं करना चाहूंगा। इस विषय पर काम करना और लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है।' अपनी फिल्मों की चॉइस पर आयुष्मान ने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है बॉलिवुड में हर ऐक्टर का एक स्पेस बना हुआ है। जैसे अक्षय कुमार देशभक्ति पर बेस्ड फिल्म करते हैं और वह फिल्में खूब सफल भी होती हैं। वैसे ही मेरी फिल्म विचित्र होती है। मुझे जब तक कोई कहानी हटकर नहीं मिलती, तब तक फिल्म में काम करने का मन नहीं होता।' आयुष्मान की फिल्म 'बधाई हो' में उनके अलावा सान्या मल्होत्रा, नीना गुप्ता, गजराज राव और सुरेखा सीकरी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 19 अक्टूबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

प्रस्तुति: भावना ओबराय

सूरत। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुहिम स्वच्छ भारत अभियान को अपना समर्थन देते हुए सूरत के नवसारी बाजार में मुसिम समुदाय के अग्रणीयों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत नवसारी बाजार में सफाई की गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रह योजना में वेटिंग ड्रो हुए आज

सूरत। प्रधानमंत्री आवस योजना केअंतर्गत सूरत महानगर पालिका के द्वारा ई.डब्लू.एस.-1 स्कीम के तहत 3118 एवं ई.डब्लू.एस-2 स्कीम के तहत 4992 आवास और कुल मिला कर 8110 आवासो का निर्मण किया जाएगा। सूरत महानगर पालिका द्वारा अभी तक ई.डब्लू.एस-1 स्कीम के तहत 3118 में से 3085 आवास और ई.एम.एस-2 स्कीम के तहत 4992 में से 4978 और कुल मिला कर 8063 आवासों का वितरण किया गया है।

पशुओ की योग्य देखभाल कर अंधश्रद्धा से दूर रहेः अनंत पटेल

वांसदा. तहसील के भिनार गांव की दूध मंडली में शनिवार को एक शिविर का आयोजन किया गया था। विधायक अनंत पटेल ने सुबह में इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को पशुओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए यह शिविर लगाया गया है। इस दौरान पशु चिकित्सक और अन्य विशेषज्ञों ने स्थानीय पशुपालकों को जानकारियां दी। विधायक अनंत पटेल ने कहा कि इस विस्तार के आदिवासी पशुपालकों ने दूध व्यवसाय शुरू कर अपना जीवन स्तर सुधारा है। उन्होंने पशुपालकों को अंधश्रद्धा से दूर रहने की सलाह देते हुए पशुओं की योग्य देखभाल पर जोर दिया। उन्होंने डेरियों में पशु डॉक्टर की नियुक्ति और पशु आहार का भाव कम करने की भी मांग की। कार्यक्रम में मौजूद नगीन भाई ने कहा कि ऐसे शिविरों से यहां के अशिक्षति पशुपालकों को नया ज्ञान मिलेगा और वह अपने पशुओं का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। इस अवसर पर तहसील पंचायत प्रमुख चंपाबेन ने कहा कि पशुपालक अपने पशुओं की सही देखभाल कर ज्यादा दूध ले सकें, इसलिए यह शिविर आयोजित किया

गया। इस अवसर पर जिला पशु नियामक डाक्टर प्रजापति, जिला पंचायत सदस्य गीताबेन, तहसील पंचायत सदस्य उत्तम भाई समेत बड़ी संख्या में पशुपालक उपस्थित थे।

गणपति बप्पा मोरिया.....

महादेव नगर गली नं. 3 उधना सूरत में विराजमान गणपित।

अंबिका नगर उधना में विराजमान गणपित (मनोकामना पूर्ण करने वाले गजराज)।

घंटीवाला काम्पलेक्ष में विराजमान गणपति।

महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव-१८ आज से

अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा कई आयोजन होंगे

सूरत. अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा महाराज अग्रसेन की ५१४२वीं जयंती पर १६ सितम्बर से जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। २१ अक्टूबर तक चलने वाले महोत्सव में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव-२०१८ का शुभारंभ रविवार को किया जाएगा। अध्यक्ष बजरंगलाल गाडोदिया ने बताया कि जयंती महोत्सव का शुभारंभ सात बजे घोड़दौड़ रोड के समाज भवन में योग-प्राणायाम से होगा। ११ बजे सोमोलाई हनुमान गौ शाला, धोरण पारड़ी, गायपगला में गौ दर्शन-पूजन, भजन, महाप्रसादी और लापसी का आयोजन होगा। इसके बाद २९ और ३० सितम्बर को गरबा, चित्रकला प्रतियोगिता और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। दो अक्टूबर को हैंडीक्राफ्ट प्रतियोगिताएं होंगी। ५ अक्टूबर को रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। ७ अक्टूबर को कंप्यूटर प्रतियोगिता, वाद-विवाद, तत्काल भाषण, मेगा हाउजी होगी।

प्रोहीबीशन केस में फरार आरोपियों को सूरत क्राईम ब्रांच ने दबोचा

सूरत। क्राईम ब्रांच ने सूरत शहर में गैर कायदेशर शराब बेचने वाले व्यक्तियों को धर दबोचा। जिसमें पुलिस कमिश्नर और पी.एस.आई एम.एस त्रिवेदी और उनकी टीम पेट्रोलिंग के समय नियोल चेक पोस्ट पे मोहिणी गाम की और रेल्वे फाटक के पास ईश्वर रमेश भाई वासफोड़ा गाम-अत्रोली,जिला-सूरत, बिना नंबर की ब्रेजा फोर व्हीलर गाड़ी में पकड़ा।

आरोपियों के पास से पुलिस ने 12 लाख की कार 2 लाख 40 रुपए नकद तथा सहित कुल रकम 14 लाख 91 हजार 270 का मुद्दा माल जब्त किया। गत 19/7/2018 को सूरत से कामरेज जाते हुए रोड पर वालक पाटीया के नजदीक संतोकबा फार्म की सामने न्यु कारकेर गेरेज के पास संजय उर्फ बटको राजुभाई मकवाणा और सागर दिनेशभाई पानसुरीया विदेशी दारु के साथ पकडे गए जिसकी कुल किमत 2 लाख 95 हजार थी। जिसके बाद दोनो आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने इन दोनों को वांटेड घोषित किया था, इन दोनों के खिलाफ सूरत, कामरेज, कड़ोदरा, पलसाणा, वापी, वलसाड़ सहित अनेक जगहों पर केश दाखिल है।

रामोल में फाइनेंसर पर तलवार और चाकू से हमले से सनसनी

अहमदाबाद। शहर के रामोल क्षेत्र में गत दिन लाकडा गैंग के शख्सों ने एक ऑफिस में घुसकर फाइनेंसर पर तलवार के द्वारा हमला करने पर पूरे क्षेत्र में भारी सनसनी मच गई है। गत दिन देर रात को लाकडा गैंग द्वारा किए गए हमले में फाइनेंसर को अंधाधुंध तलवार और चाकू से वार करके ४० हजार रुपये लूट लिए। घटना की वजह से स्थानीय निवासियों में भारी दहशत फैल गई है। सीटीएम क्षेत्र में स्थित नीलकंठ सोसाइटी में रहते और सिंधवाईनगर में स्थित सुभाष कॉम्प्लेक्स में फाइनेंस की ऑफिस वाले नवनीत हीरालाल सोनी ने रामोल पुलिस स्टेशन में लाकडा गैंग के मुख्य सूत्रधार सहित ६ लोगों के विरूद्ध में हत्या की कोशिश शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गत दिन रात को नवनीत और उनका मित्र ऑफिस में बैठा था उस समय में कार और बाइक पर हथियार लेकर लाकडा गैंग के असामाजिक तत्व पहुंच गये। लाकडा गैंग के शख्सों में योगेश दद्दा, अरुण चौहाण, अभिषेक राजपूत, निखिल कांचो, अर्जुन मद्रासी और सरदारसिंग राजपूत नवनीत की ऑफिस में घुसकर इस पर हिंसक हमला कर दिया। सभी लोग तलवार और चाकू लेकर आये थे। नवनीत कुछ भी समझे उसके पहले ही हमला करना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने अंधाधुंध तलवार और चाकू से नवनीत पर हमला करके इसे घायल कर दिया और इसके बाद ४० हजार रुपये लूट लिए। नवनीत को छुड़ाने के लिए बीच में आये उनके मित्र पर भी सभी लोगों ने हमला कर दिया। घायल हालत में नवनीत को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। एक वर्ष पहले रुपये के लेन-देन मामले में अरुण ने नवनीत का अपहरण किया गया। अरुण और इसके साथियों ने नवनीत का अपहरण करने के बाद इसे सूनसान जगह पर ले गये, जहां उसकी पिटाई की गई और उसके बाद छोड़ दिया गया। इस मामले में नवनीत ने रामोल पुलिस स्टेशन में अरुण और इसके साथियों के विरूद्ध में अपहरण की शिकायत की थी।

महादेव मीडिया
रोहताश यादव 9924144499, 7015339195
वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)
हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।
304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com